an>

Title: The Minister of External Affairs made a statement regarding the Prime Minister's recent visits abroad.

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किये गये विदेश के दौरों और सदन के पिछले सत्र के बाद से हमारे विदेशी सम्बन्धों में विस्तार पर मैं एक वक्तव्य देना चाहती हूँ।

अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि भारत में सम्पन्न हुए ऐतिहासिक आम चुनावों ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रति एक नई रूचि जागृत की है और विश्व का भारत में विश्वास फिर से बहाल हुआ है। जब विश्व अनिश्चय और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गठित भारत की नई सरकार ने विश्व में नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीव्र गति से विकास की आशा को अभूतपूर्व बल मिला है और विश्व में शान्ति, स्थायित्व और सम्पन्नता के लिए भारत के व्यापक, असरदार और सार्थक योगदान के प्रति एक नई आशा जगी है।

अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी ने सदा एक ऐसी विदेश नीति पर बल दिया जो आगे बढ़कर विश्व मामलों में सक्रियता दिखाने और अभिनव प्रयोगों से युक्त हो और जो हमारी सरकार के आर्थिक विकास के प्राथमिक उद्देश्य से सम्बद्ध हो। पूँजी, प्रौद्योगिकी, संसाधन, ऊर्जा, बाजार और दक्षता के लिए भारत को आज एक सुरक्षित परिवेश, शान्तिपूर्ण पड़ोस, स्थायित्वपूर्ण विश्व और एक खुली और मजबूत विश्व व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता है। हमारी नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सभी को साथ लेकर चलने की चिरकालीन परम्परा से जुड़ी हुई है और वसुधैवकुटुम्बकम के आदर्श से प्रभावित है।

भारत की विदेश नीति ने नए मुकाम हासिल किए हैं और नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारे इन प्रयासों पर विश्व ने अभूतपूर्व प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

अध्यक्ष महोदया, संसद के पिछले सत्र के बाद प्रधानमंत्री जी ने जापान, अमेरिका, म्यांमार, आस्ट्रेलिया, फीजी और नेपाल की यात्रा की और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में भाग लिया। हमारे लिए यह सम्मान की बात है कि आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी ऐबट और चीन के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने सितम्बर माह में भारत की यात्रा की। पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सभी महाद्वीपों के 45 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने भारत-आसियान, पूर्वी एशिया, जी-20 और सार्क शिखर वार्ताओं में भाग लिया। ये सभी शिखर वार्ताएं हमारे क्षेत्र, एशिया और विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फीजी प्रशांत महासागर क्षेत्र का एक प्रभावी राष्ट्र है और इसकी 37 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, फिर भी, आप हैरान होंगे, पिछले 33 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली फीजी यात्रा थी। फीजी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ऐसे पहले भारतीय नेता बने जिन्होंने प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं के साथ बैठक की। प्रशांत महासागर देशों के राष्ट्र हमारी चुनौतियों में हमारे साझेदार हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं। इस अनुपम पहल को प्रशांत महासागर देशों के नेताओं ने हृदय से सराहा। यह भविष्य में इन देशों के साथ हमारे सतत् सहयोग की शुरूआत है।

प्रधानमंत्री जी को आस्ट्रेलिया की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का गौरव प्राप्त हुआ - वे इस प्रकार का गौरव प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। साथ ही वे फीजी द्वीप में नए संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र की बहाली के बाद चुनी गई संसद को संबोधित करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता बने। दोनों संबोधनों को मेजबान देश और विश्व भर में खूब सराहा गया।

प्रत्येक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों से मुलाकात की, जिसे पहले किसी भारतीय नेता की यात्रा के दौरान नहीं देखा गया। यह हमारे उस विश्वास को परिलक्षित करता है जिसमें आधुनिक काल में राष्ट्रों के बीच संबंध उनकी राजधानियों और आधिकारिक मुलाकातों से कहीं आगे बढ़कर है।

अध्यक्ष जी, हमारे विदेशी संबंध मात्र गौरव का प्रतीक ही नहीं हैं, अपितु यह परिणामों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि हम जापान के साथ अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर तक ले गए हैं। चीन के साथ बकाया मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी में गति को बहाल किया है। आस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को एक नई दिशा दी है और हिचकिचाहट भरी " लुक ईस्ट " नीति को " एक्ट ईस्ट " नीति में तब्दील किया है।

हमारी सरकार अगले दौर के सुधारों के जरिए आधारभूत ढांचे और निर्माण क्षेत्र को विकसित करने की तैयारी में है। ऐसे समय में हमें जापान से अगले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 3.5 खरब येन - तकरीबन 35 अरब अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता की वचनबद्धता मिली है। चीन के साथ हमने दो औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करने और 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के समझौते किए हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान अमेरिकी कंपनियों द्वारा 42 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश की आशा है।

ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

हमने नेपाल के साथ साझेदारी के एक नए युग में प्रवेश किया है जिसका हमें सदियों से इंतजार था। नेपाल के साथ महाकाली संधि के दो दशकों के पश्चात 5600 मेगावाट वाली बहुउद्देशीय पंचेश्वर परियोजना हेतु हमने पंचेश्वर विकास प्राधिकरण का गठन किया है।

इसके अलावा हमने नेपाल के साथ एक नया ऊर्जा व्यापार समझौता किया है। दो भारतीय कंपनियों को 900-900 मेगावाट जलविद्युत उत्पन्न करने का परियोजना लाइसेंस मिला है। दोनों देशों के लोगों के लिए यात्रा और पर्यटन को सुगम बनाने के लिए मोटर वाहन समझौता किया है जो काफी समय से लंबित था।

अध्यक्ष जी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत से विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सुरक्षा के हमारे हितों की रक्षा और दोहा विकास चक्र की बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस पहल से विश्व व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली है जो भारत के हित में है और साथ ही हमने गरीबों के हितों की रक्षा हेतु उनके प्रति हमारे मौलिक दायित्वों में किसी प्रकार की कमी किये बिना भारत के हितों की रक्षा की है।

हमारा ध्यान केवल निर्माण और आधारभूत ढांचे पर ही केंद्रित नहीं है। विदेशों में प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्र हित के बिन्दुओं पर भी ज़ोर दिया है। जैसे- दक्षता के विकास में सहयोग को आगे बढ़ाना, बीमारियों से लड़ने के लिए उन्नत चिकित्सीय अनुसंधान में सहयोग जैसे मलेरिया और टीबी के अनुसंधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता करना, जैसे खाद्य सुरक्षा जैसे हमारे किसानों के फायदे के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ कृषि अनुसंधान में सहयोग करना, जैसे शिक्षा जैसे अगले दौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग पर समझौता करना, और भारत में पढ़ाने के लिए 1000 उच्च अमेरिकी प्राध्यापकों को भारत लाने की योजना बनाना।

अध्यक्ष जी, क्योटो-वाराणसी के बीच विकासात्मक सहयोग की व्यवस्था, अहमदाबाद-ग्वांगजू और मुम्बई-शंघाई शहरों के बीच सहयोग संबंधी समझौते और अमेरिका के साथ तीन स्मार्ट शहरों को विकसित करने की योजना ऐसी है, जिससे भारत के तीव्र शहरीकरण के अवसरों पर काम किया जा सके और इससे उत्पन्न चुनौतियों को सुलझाया जा सकेगा।

अध्यक्ष जी, बहुराष्ट्रीय और क्षेत्रीय फोरम हमारे राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के बहुत महत्वपूर्ण मंच हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रधान मंत्री जी का हिन्दी में संबोधन भारत के लिए राष्ट्रीय गर्व का विषय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के उनके आह्वान से इस दिशा में हमारे द्वारा किये जा रहे प्रयासों को गति मिली है और उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के आह्वान को व्यापक समर्थन मिला है।

अध्यक्ष जी, ब्रिस्बेन में जी-20 राष्ट्रों की शिखर वार्ता के दौरान भारत में आर्थिक सुधारों को लेकर अत्यधिक उत्साह दिखा। प्रधान मंत्री जी ने काले धन के खिलाफ सामूहिक रूप से अन्तरराष्ट्रीय कार्यवाही पर बल दिया। उन्होंने विकासशील देशों में अवसंरचनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए कम खर्च वाले सामूहिक प्रयासों और नवीन समाधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया और नवीकरणीय ऊर्जा पर एक नई वैश्विक पहल का प्रस्ताव किया। उन्होंने क्षेत्रीय व्यापार समझौतों और विश्व व्यापार समझौतों के राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का माध्यम बनने और गुटों में बंटने के खतरे

की ओर भी ध्यान दिलाया।

दस राष्ट्रों का आसियान समूह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी इन राष्ट्रों में रहती है और भारत और चीन के बाद यह दुनिया की तीव्र गति से विकसित हो रही तीसरी अर्थव्यवस्था है। म्यांमार में भारत-आसियान शिखर वार्ता में हमारे आसियान के सहयोगियों के मध्य इस बात को लेकर एक नयी आशा और उत्साह था कि नवीन सुधारों से युक्त भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और आसियान राष्ट्र समूह के मध्य एक गहरी साझेदारी की नींव रखेगी, जिससे हमारे इस साझा क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और संपन्नता का एक नया दौर शुरू होगा।

प्रधान मंत्री जी ने ने-पी-दॉ की इस यात्रा का लाभ उठाते हुए हमारे इस महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र म्यांमार के नेतृत्व के साथ मजबूत साझेदारी की अपनी वचनबद्धता दोहराई।

अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी का हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ साझा भविष्य में मजबूत विश्वास है जो उनके द्वारा उठायी गयी कई ठोस पहलों से परिलक्षित होता है - पड़ोसी राष्ट्रों के नेताओं का 26 मई के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना, अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुनना, नेपाल की उनकी यात्रा जो पिछले सतूह वर्षों में भारत के किसी प्रधान मंत्री की हमारे इस पड़ोसी राष्ट्र की पहली यात्रा थी।

काठमांडू में 26-27 नवम्बर के बीच आयोजित 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी ने दक्षिण एशिया में साझा संपन्नता के अपने दृष्टिकोण को रखा। उन्होंने इस क्षेत्र के सबसे बड़े राष्ट्र और इसके मध्य में स्थित राष्ट्र होने के कारण इस क्षेत्र में आपसी सहयोग और दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य सार्क के माध्यम से और इसके बाहर सामंजस्यता विकसित करने की ओर भारत के मजबूत इरादों की तरफ ध्यान दिलाया। प्रधान मंत्री जी के दृष्टिकोण और इस क्षेत्र के लिए की गयी पहलों से दक्षिण एशिया के हमारे सदस्य राष्ट्रों के मध्य एक नयी आशा का संचार हुआ है। अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी ने कई अवसरों पर यह कहा है कि हम अपने विकसित भविष्य की नींव एक सुरक्षित भारत पर ही रख सकते हैं।

प्रत्येक अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक स्थाई और शांतिपूर्ण एशिया और इसके आस-पास के समुद्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्वीकार्यता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें समुद्रीय सुरक्षा भी शामिल है। प्रधानमंत्री जी ने साइबर सुरक्षा और अन्तरिक्ष सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए खतरे की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया।

प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम एशिया में इस्लामिक राष्ट्र के उभार और इससे विश्व पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ताओं को साझा किया। उन्होंने आतंकवाद के वैश्विक खतरे से निबटने के लिए एक व्यापक नीति बनाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ विभिन्न आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों को अलग-थलग करने के लिए विश्व स्तर पर एक व्यापक नीति बनाने की सलाह दी, जिससे कि इन आतंकवादी गुटों के प्रायोजकों को अलग-थलग किया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले राष्ट्रों की मदद का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद को धर्म से अलग रखने और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के एकजुट होने पर बल दिया। हमारे विदेशी आदान-प्रदानों से मुख्य सहयोगियों के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में मदद मिली है।

अध्यक्ष महोदया, विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय में जोश, ऊर्जा और विश्वास, चुनाव के बाद के राष्ट्रीय माहौल को परिलक्षित करता है। प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में बसे भारतीय समुदाय तक उस स्तर तक पहुंच बनाने की कोशिश की और उस स्तर तक पहुंच बनाने की ओर ध्यान दिया है, जिसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। विदेशों में स्थित भारतीय समुदाय द्वारा पी आई ओ और ओ सी आई कार्डों पर हमारे निर्णयों को व्यापक रूप से सराहा गया है। आज भारतीय समुदाय न केवल अपने को भारत से जुड़ा हुआ महसूस करता है, बल्कि उसने भारत में बदलाव की पहल में अपनी सहभागिता को भी सकारात्मक रूप में स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विश्व में भारत की भूमिका और स्थान को लेकर एक स्पष्ट दृष्टि रखी है, जिसमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते विश्व नेतृत्व को ग्रहण करने की अपनी स्वीकार्यता भी शामिल है। हमने वादों को कार्यवाही में, अवसरों को परिणामों में बदला है। हमने उन सम्बन्धों को पुनर्जीवित किया है, जो लंबे समय से उपेक्षित पड़े थे। हमने अपने सुरक्षा हितों को खुलकर व्यक्त किया है और जोरदार तरीके से उनकी रक्षा की है।

आज भारत को लेकर विश्व में एक नया विश्वास है। प्रधानमंत्री जी के विदेश दौर से विकास के हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सुरक्षित और स्थायी वातावरण बनाने में मदद मिली है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इससे हमें आर्थिक विकास, निवेश को बढ़ावा देने, नये रोजगार के सृजन करने और हमारे लोगों के जीवन में सुधार लाने के हमारे मिशन को हासिल करने में बहुत-बहुत मदद मिलेगी।